



2 देश-विदेश

फरीद जकारिया का येल की प्रशासन समिति से इस्तीफा



4 विचार-प्रवाह

तैयार हो रहा है मोहभंग का जनमत

7 खेल

शीर्ष टीमों के लिए लगातार खेलना होगा: संदीप सिंह



पेज श्री समाचार पत्र अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध पढ़ने के लिए कृपया लॉगऑन करें:-
www.page3news.in



सरकारी नौकरियों में बढ़ी आयु सीमा

देहरादून। उत्तराखण्ड की कांग्रेस सरकार ने गत विधानसभा चुनावों में बेरोजगारों से कये गये वायदे को निभाते हुये सरकारी नौकरियों के लिये आयु सीमा बढ़ाने के साथ ही प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था की बदहाली में सुधार के लिये डाक्टरों के वेतन में लगभग दोगुनी वृद्धि कर दी है। बहुगुणा सरकार ने शिक्षण संस्थाओं से आरएसएस नेताओं के नाम हटाने के साथ ही 6000 मेगावाट की अन्तराष्ट्रीय महत्व की पंचेश्वर बिजली परियोजना को भी अपनी सहमति दे दी है।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

चिकित्सकों के वेतन में हुआ इजाफा(हजार रुपये में)	साधारण	डिप्लोमाधारी	पीजी विशेषज्ञ
सुगम	48	52	55
दुर्गम	52	56	59
अति दुर्गम	56	60	63

राजकीय सेवाओं में सामान्य वर्ग को राहत, आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष हुई। आरक्षित वर्ग रहेंगे पूर्ववत्।

पत्रकारों की अनुग्रह राशि 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये

प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक में नई भर्ती ब्लॉक केडर के आधार पर

रीवर राफिटिंग को प्रोत्साहन, कैपिंग पॉलीसी को मंजूरी

खादी के वस्त्रों पर वैट में छूट

स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त स्कूल कैंब पर कर की दरों पर मिलेगी छूट

संबंधित समाचार पृष्ठ 8 पर

मुंबई हिंसा के पीछे बांग्लादेशी: राज ठाकरे



इन लोगों को यहां आकर यहां का माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी

मुंबई ।। राज ठाकरे ने 11 अगस्त को मुंबई में हुई हिंसा का ठीकरा भी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पर फोड़ते हुए कहा कि इस हिंसा में कोई भी महाराष्ट्र का आदमी नहीं था। उन्होंने कहा कि उस हिंसा में शामिल सारे लोग बाहरी राज्यों के थे। उन्होंने कहा कि आम मराठी माणूस हिंसा में विश्वास नहीं करता।

राज ने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र के पुलिस वालों पर और यहां के लोगों पर जब कभी हमला होगा तो मैं ऐसे ही उसके पक्ष में खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि रेलोग धर्म का सवाल उठा रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही धर्म है महाराष्ट्र धर्म। कोई और धर्म मैं नहीं जानता। जिन पुलिस वालों पर उस दिन

बाहरी लोगों के सिर पर फोड़ा ठीकरा

हमला हुआ था, जिन महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी हुई थी, वे सब महाराष्ट्र के हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया वे बाहर से आए हुए लोग थे। उन्होंने कहा कि जो कोई भी पुलिस पर हाथ उठाए उसे वहीं के वहीं काट देना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो।

राज ठाकरे ने कहा कि यूपी और बिहार से काफी लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग मुंबई में छिपे हुए हैं। राज ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर आर पाटील और मुंबई के पुलिस कमिश्नर अरुण पटनायक पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन दोनों को तुरंत पद से हटाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया जब हमला हो रहा था तब आर आर पाटील कहाँ थे? पटनायक की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जब एक डीसीपी ने एक गुनहवार को पकड़ा तो पटनायक ने उसे छोड़ने का आदेश दिया। आखिर हमला करने वालों के प्रति इतना ढीला रवैया दिखाने वाले शख्स को पुलिस कमिश्नर कैसे बनाए रखा जा सकता है?

प्रणव मुखर्जी के राष्ट्रपति चुने जाने को संगमा ने दी चुनौती



नामांकन दाखिल करते वक्त प्रणव मुखर्जी लाभ के पद पर आसीन थे: संगमा

नई दिल्ली ।। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पी. ए. संगमा ने राष्ट्रपति पद पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणव मुखर्जी के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट में आज चुनौती दे दी। राष्ट्रपति पद के लिए 19 जुलाई को हुए चुनाव में प्रणव मुखर्जी ने संगमा को पराजित किया था। संगमा ने चुनाव याचिका में तर्क दिया है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते वक्त प्रणव मुखर्जी लाभ के पद पर आसीन थे। याचिका में

दावा किया गया है कि प्रणव भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसओ) के अध्यक्ष पद पर आसीन थे। संगमा के चुनाव प्रचार के प्रभारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतपाल जैन ने बताया कि इस याचिका में राष्ट्रपति पद पर प्रणव मुखर्जी का निर्वाचन निरस्त करने का न्यायालय से आग्रह किया गया है। संगमा चाहते हैं कि प्रणव का निर्वाचन निरस्त करके उनके स्थान पर उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाए।

- न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण किया जाए
- श्रमिकों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, कार्यवाई की मांग



एटक का रोष

पीएम के इस्तीफे की मांग को कांग्रेस ने खारिज किया

नई दिल्ली ।। कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितता की निर्यंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैंग) की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग को सिरे से खारिज करते हुए सरकार ने बीजेपी से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने को कहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अबिका सोनी ने संसद भवन परिसर में कहा कि बीजेपी बिना किसी सुबूत के प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। यह पहली बार नहीं है जब विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रही है, संसद के हर सत्र में इस प्रकार की मांग करना उसका चलन हो गया है।

किसानों पर दर्ज मुकदमें वापस होंगे

किसान महापंचायत 27 को होगी

लखनऊ। यमुना एक्सप्रेस-वे समेत अन्य मसलों पर 27 अगस्त को नोएडा में आयोजित महापंचायत की जानकारी देते हुए भाकियू प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री से हुई वार्ता के बारे में किसानों को बताया जाएगा और आगे की रणनीति तय होगी। इस के अलावा किसानों और सरकार के बीच नियमित संवाद बनाने को जिले स्तर पर बैठक कराने के बारे में चर्चा होगी।

बिजली और पानी देने जैसे तमाम वादे पूरे करने का संकल्प भी दोहराया। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में राजपाल शर्मा, दीवान चंद, बलराम लम्बरदार, राजेश चौहान व धर्मेन्द्र मलिक समेत दर्जन भर किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से उनके आवास पर करीब एक घंटा चली वार्ता के बाद संतुष्ट नजर आया।

बकाया गन्ना मूल्य न मिलने के कारण चीनी मिलों पर ताले डालने की चेतावनी देने वाले भाकियू नेता तीन सप्ताह में मुश्तान चुकता करा देने के आश्वासन पर मान गए।

कुछ हटके

ब्यूरोक्रेट्स की नीतियों से उबरे संविदा शिक्षक

खबर का असर

की दलीलों को देखते हुए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड एके जैन को निर्देशित किया कि नये सिरे से संविदा शिक्षकों के चयन को आयोजित सभी साक्षात्कार निरस्त किये जाने के आदेश सभी पॉलीटेक्नीकों को भेज दिये जायें साथ ही पॉलीटेक्नीकों में कार्यरत सभी 110 संविदा शिक्षकों को नियमानुसार सेवा विस्तार दिया जाय। इधर राजकीय पॉलीटेक्नीक संविदा शिक्षक सोसाइटी के अध्यक्ष सोमनाथ टोडरिया और उपाध्यक्ष पंकज सैलानी ने मुख्यमंत्री को दूरभाष पर वार्ता के दौरान बताया कि ब्यूरोक्रेट्स की मनमानी की वजह से लोकसेवा आयोग को साक्षात्कार के लिए भेजे गये 198 पदों में कार्यरत 110 शिक्षकों के पदों को भी शामिल कर दिया गया जिससे उनका

भविष्य अधर में है। हालांकि इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कोई निर्देश नहीं दिये अलबत्ता उन्होंने प्रमुख सचिव को संविदा शिक्षकों के मसले पर नीति निर्धारित किये जाने के भी निर्देश दिये। फिलहाल मुख्यमंत्री के निर्देश से संविदा शिक्षकों नौकरियों पर छाया संकट फिलहाल टल गया है। लेकिन अब संविदा शिक्षक तदर्थ नियुक्ति की मांग को ले कर एक बार फिर मुख्यमंत्री की खड़ोटी पर दस्तक देने का मन बना चुके हैं।



- मुख्यमंत्री ने संविदा शिक्षकों के साक्षात्कार किये निरस्त
- पॉलीटेक्नीकों में कार्यरत 110 संविदा शिक्षकों को दिया सेवा विस्तार